

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस के तहत "कंप्लायंस रिडक्शन एवं डीरेगुलेशन" में राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका
2.	भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान मण्डप का किया उद्घाटन (आईआईटीएफ- 2025)
3.	उदयपुर में संभागीय सहकार मेले और आदि हाट का शुभारंभ
4.	एचसीएम- रीपा का 69वाँ स्थापना दिवस समारोह
5.	"आपकी पूँजी, आपका अधिकार" अभियान के तहत जिला स्तरीय शिविर का हुआ आयोजन
6.	मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा: फिरोजपुर फीडर रिलाइनिंग परियोजना
7.	संजय अग्रवाल महानिदेशक लॉ एण्ड ऑर्डर नियुक्त
8.	अंता उपचुनाव: भाया की जीत ने बदल दिए सत्ता और विपक्ष के समीकरण
9.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. शिक्षा जैन को ऑल एज वर्ल्ड एमेच्योर गोल्फ रैंकिंग में दूसरा स्थान
10.	मुध-न्योमा एयरबेस
11.	भारत और नेपाल संबंध
12.	सारंडा वन
13.	जलवायु वित्त-पोषण लक्ष्य
14.	जलवायु परिवर्तन पर सूचना अखंडता पर घोषणा
15.	ऑरोरा
16.	महत्वपूर्ण खनिजों की नई रॉयल्टी दरें
17.	वैश्विक कार्बन बजट 2025
18.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट, 2025 2. प्रत्यूष सिन्हा समिति



राजस्थान परिदृश्य



ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस के तहत "कंप्लायंस रिडक्शन एवं डीरेगुलेशन" में राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका



चर्चा में क्यों?

- कैबिनेट सचिव डॉ. टी. वी. सोमनाथन ने देशभर के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से "कंप्लायंस रिडक्शन एवं डीरेगुलेशन" एजेंडा के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा की।



मुख्य बिन्दु:

- राजस्थान ने ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस इकोसिस्टम को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए कई परिवर्तनकारी सुधार लागू किए हैं-
- एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने नियम 90ए में संशोधन कर चेंज ऑफ़ लैंड यूज प्रक्रिया को सरल बनाया है, जिसके तहत समय सीमा 60 से घटाकर 30 कार्य दिवस कर दी गई है। इस समय सीमा के बाद स्वतः स्वीकृति का प्रावधान किया गया है। इससे परियोजनाओं में होने वाली देरी में कमी आएगी और नए उद्यमों की स्थापना तेजी से होगी।
- **प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में-** एमएसएमई के लिए कंसेट टू एस्टैब्लिश और कंसेट टू ऑपरेट हेतु थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की समय सीमा 120 दिनों से घटाकर 21 दिन और रेड / वृहद् श्रेणी के उद्यमों के लिए 60 दिन कर दी गई है।
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर सभी श्रेणियों में सीटीओ का सिस्टम-जनरेटेड ऑटो रिन्यूवल शुरू किया है।

Daily Current Affairs

Date : 15 November, 2025



- 'राजस्थान शॉप्स एण्ड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, 1958' के अंतर्गत कर्मचारियों की सीमा शून्य से बढ़ाकर 10 कर दी गई है, जिससे सूक्ष्म उद्यमों पर अनुपालन बोझ कम हुआ है।
- राज्य ने थर्ड पार्टी फायर इंस्पेक्टर को भी लागू किया है और फायर एनओसी की वैधता अवधि बढ़ाई है, जिससे फायर सुरक्षा कंप्लायंस को सुगम बनाया गया है।
- राज्य की सिंगल विंडो प्रणाली 'राजनिवेश' को चैटबॉट के साथ उन्नत किया गया है, जो विभिन्न विभागों की जानकारी को एकीकृत कर निवेशकों को रियल टाइम स्वचालित सहायता प्रदान करता है।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--3--

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान मण्डप का किया उद्घाटन(आईआईटीएफ- 2025)

चर्चा में क्यों?

- नई दिल्ली में 14 दिवसीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान पार्टनर स्टेट है। राजस्थान मण्डप को 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की थीम पर तैयार किया गया है।



मुख्य बिन्दु:

- "एक भारत श्रेष्ठ भारत" की भावना को समर्पित राजस्थान मण्डप में राजस्थान और असम का एकीकरण एक प्रमुख आकर्षण है। इस विशेष पहल के माध्यम से दोनों राज्यों की संस्कृति, कला और व्यापारिक संभावनाओं का आदान-प्रदान किया गया है, जिससे इन दोनों राज्यों के बीच मजबूत व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित होंगे।
- राजस्थान मण्डप में कारीगरों एवं उद्यमियों द्वारा लाइव प्रदर्शन आयोजित किये जाएंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल एवं राज्य की विरासत, नवाचार और सतत औद्योगिक विकास आधारित प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा।
- भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान हर वर्ष की भाँति इस वर्ष भी 18 नवंबर को राजस्थान दिवस मनाया जाएगा, जिसमें रंगारंग सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा।

उदयपुर में संभागीय सहकार मेले और आदि हाट का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

- सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष तथा जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा के उपलक्ष्य में उदयपुर में सहकारिता विभाग के तत्वावधान में आयोजित 3 दिवसीय संभाग स्तरीय सहकार मेला एवं 'आदि हाट' का शुभारम्भ किया।



- **थीम:** "परिचालन दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने हेतु डिजिटलीकरण को बढ़ावा"

मुख्य बिन्दु:

- य सहकार सदस्यता अभियान के दौरान पूरे प्रदेश में 9 लाख लोगों को सहकारिता से जोड़ा गया तथा 2200 से अधिक नए पैक्स गठित की गई।
- कार्यक्रम के दौरान 72वें अखिल भारतीय सहकार सप्ताह की शुरुआत की गई।
- ई-पैक्स सर्टिफिकेट एवं माइक्रो एटीएम का वितरण-डिजिटल लेनदेन को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न संस्थानों को ई-पैक्स सर्टिफिकेट और माइक्रो एटीएम भी वितरित किए गए।
- वैश्विक स्तर पर सहकारिता आंदोलन की सूची में पहले स्थान पर अमूल तथा दूसरे पर इफको है। ह माँक ड्रिल राजस्थान और मध्य प्रदेश

एचसीएम- रीपा का 69वाँ स्थापना दिवस समारोह

चर्चा में क्यों?

- हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (ओ.टी.एस.) का 69वाँ स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ भगवत सिंह मेहता सभागार में संस्थान की महानिदेशक एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव (प्रशिक्षण) श्रीमती श्रेया गुहा ने किया।



मुख्य बिन्दु:

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- यह हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एचसीएम रीपा) की स्थापना 1957 में हुई थी, यह संस्थान मूल रूप से जोधपुर में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल (OTS) के नाम से स्थित था। बाद में इसे जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया।
- अखिल भारतीय एवं राज्य प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों के सेवा पूर्व, मिड टर्म और ओरिएंटेशन प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है।
- इस अवसर पर 'स्वच्छ रीपा कार्यक्रम' के माध्यम से संस्थान परिसर में साफ-सफाई कार्य कर श्रमदान किया गया।
- इस अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस, 29 अगस्त, 2025 पर आयोजित खेलकूद विजेताओं को पुरस्कृत तथा अतिथि कलाकारों का सम्मान किया गया। मॉक ड्रिल राजस्थान और मध्य प्रदेश

“आपकी पूँजी, आपका अधिकार” अभियान के तहत जिला स्तरीय शिविर का हुआ आयोजन

चर्चा में क्यों?

- केन्द्रीय वित्तीय सेवाएँ विभाग देशभर में 'आपकी पूँजी, आपका अधिकार' जन-जागरूकता अभियान चला रहा है। इसके तहत जयपुर में राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, दुर्गापुरा में जिला स्तरीय जागरूकता एवं सहायता शिविर का आयोजन किया गया।



मुख्य बिन्दु:

उद्देश्य:

- इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को उनकी जमा पूँजी, बीमा दावों, डिविडेंड, शेयर एवं म्यूचुअल फंड से संबंधित अनक्लेम्ट राशि को प्राप्त कराने में सहायता प्रदान करना है।
- कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए।
- शिविर में विभिन्न बैंकों, बीमा कंपनियों, पेंशन विभाग एवं सेबी द्वारा सूचना एवं सहायता काउंटर स्थापित किए गए, जहाँ नागरिकों को केवाईसी अपडेट, दावा प्रपत्र भरने, दस्तावेज़ सत्यापन सहित सभी आवश्यक प्रक्रियाओं में सहयोग प्रदान किया गया।
- अभियान के अंतर्गत आगामी 31 दिसम्बर तक पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक जिले में जागरूकता एवं सहायता शिविर आयोजित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा: फिरोजपुर फीडर रिलाइनिंग परियोजना

चर्चा में क्यों?

- मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल, केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी से मुलाकात की।



मुख्य बिन्दु:

- फिरोजपुर फीडर रिलाइनिंग एवं रामजल सेतु लिंक परियोजना की प्रगति को लेकर चर्चा हुई।
- किसानों के हित में टॉवर बेस मुआवजा दर को डी.एल.सी. दर के 400 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है जबकि कॉरिडोर मुआवजा ग्रामीण क्षेत्रों में 30 प्रतिशत, नगरपालिका क्षेत्रों में 45 प्रतिशत तथा नगर निगम क्षेत्रों में 60 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।
- बैठक में राजस्थान में भारत के सौर ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने की अपार संभावनाओं को देखते हुए विद्युत निकासी के सुदृढीकरण को लेकर सार्थक चर्चा की गई।
- ए.टी. एण्ड सी. हानियों में लगातार कमी आ रही है। इसी क्रम में जयपुर एवं अजमेर डिस्कॉम अब 15 प्रतिशत के स्तर से नीचे आ चुके हैं। साथ ही, आर.डी.एस.एस. योजना के क्रियान्वयन की गति में सुधार किया गया है।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु :

- फिरोजपुर फीडर रिलाइनिंग परियोजना (Firozpur Feeder Relining Project) राजस्थान और पंजाब के लिए एक महत्त्वपूर्ण जल एवं सिंचाई संरचना का पुनरोद्धार कार्य है, जिसकी मुख्य बातें निम्न हैं:

परियोजना का उद्देश्य

- फिरोजपुर फीडर एक प्रमुख नहर है, जो पंजाब के हरिके बैराज से शुरू होकर राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ आदि जिलों में गंग नहर एवं अन्य नहर प्रणालियों को जल उपलब्ध कराती है।
- पिछले कई वर्षों में इसका अस्तर (lining) क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे पानी का रिसाव, जलभराव, शक्तिहीन प्रवाह और जल वितरण में असमानता उत्पन्न हो गई थी।
- वर्ष 1960: फिरोजपुर फीडर का निर्माण पूरा हुआ था।
- अप्रैल 24, 2025: केंद्रीय जल आयोग की 158वीं सलाहकार समिति ने परियोजना की मंजूरी दी।
- 2027 (लक्ष्य): दो वर्षों में पूर्ण निर्माण; क्षमता 11,192 क्यूसेक से बढ़कर 13,842 क्यूसेक करना।

संजय अग्रवाल महानिदेशक लॉ एण्ड ऑर्डर नियुक्त

चर्चा में क्यों?

- राजस्थान सरकार ने 14 नवंबर, 2025 को पुलिस विभाग में महानिदेशक (D.G.), कानून और व्यवस्था (DG Law and Order) का नया पद सृजित किया है। संजय अग्रवाल इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले अधिकारी हैं।



मुख्य बिन्दु:

- राजस्थान पुलिस के मुखिया (DGP) राजीव कुमार शर्मा ने एक आदेश जारी कर डीजी अग्रवाल को तीन विंग की जिम्मेदारी सौंपी है। अग्रवाल कानून-व्यवस्था के साथ आरएसी आर्ड बटालियन व एसडीआरएफ की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन इस विंग के अलावा उन्हें साइबर क्राइम और तकनीकी सेवाओं का सुपरविजन करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

अंता उपचुनाव: भाया की जीत ने बदल दिए सत्ता और विपक्ष के समीकरण

चर्चा में क्यों?

- 11 नवंबर, 2025 को बारां जिले की अंता सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद भाया ने जीत हासिल की हैं। परिणाम(14 नवंबर, 2025)।

जीत : प्रमोद जैन भाया (कांग्रेस)	हार : मोरपाल सुमन (भाजपा)	3 नंबर पर : नरेश मीणा (निर्दलीय)
		
मत मिले : 69,571 15612 मतों से जीते	मत मिले : 53,959 15612 मतों से हारे	मत मिले : 53,800 15771 मतों से हारे

मुख्य बिन्दु:

उपचुनाव का कारण:

- अंता विधानसभा सीट से भाजपा विधायक कँवरलाल मीणा को 2005 के एक मामले में 3 साल की सजा होने पर 1 मई, 2025 को उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी।

सदस्यता रद्द होने के प्रावधान:

1. RPA Act, 1951 के तहत:

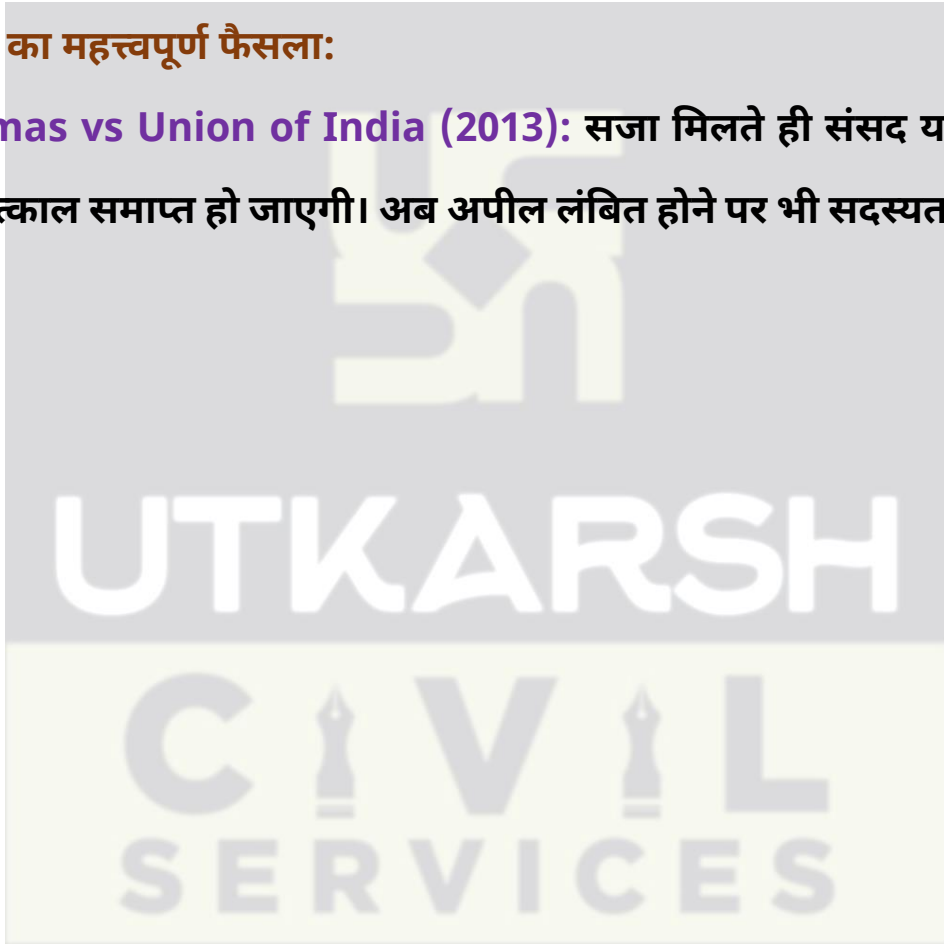
- Section 8(3) - जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951:** अगर किसी विधायक (MP/MLA) को किसी अपराध के लिए न्यूनतम 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है, तो उसे सजा के दिन से सदस्यता समाप्त हो जाती है और सजा पूरी होने के छह साल बाद तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य रहता है।

Daily Current Affairs

Date : 15 November, 2025



- **Section 8(4) (अब समाप्त):** पहले सजा के खिलाफ ऊँचे न्यायालय में अपील करने पर तीन माह की छूट मिलती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2013 के Lilly Thomas केस में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, जिससे सजा मिलते ही सदस्यता समाप्त होती है, चाहे अपील लंबित हो।
- 2. **सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला:**
 - **Lily Thomas vs Union of India (2013):** सजा मिलते ही संसद या विधानसभा सदस्यता तत्काल समाप्त हो जाएगी। अब अपील लंबित होने पर भी सदस्यता नहीं बचती।



✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>शिक्षा जैन को ऑल एज वर्ल्ड एमेच्योर गोल्फ रैंकिंग में दूसरा स्थान</p>  <ul style="list-style-type: none">गोल्फ स्टार शिक्षा जैन ने IGU महाराष्ट्र लेडीज एवं जूनियर गर्ल्स गोल्फ चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस शानदार प्रदर्शन के चलते शिक्षा जैन को ऑल एज वर्ल्ड एमेच्योर गोल्फ रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। टूर्नामेंट में शिक्षा ने 16वें होल पर ईगल और 17वें होल पर बर्डी बनाई, जिससे उनकी स्थिति मजबूत हुई। शिक्षा जैन जयपुर से हैं और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर की जूनियर गोल्फ चैंपियन हैं।



राष्ट्रीय परिदृश्य



मुध-न्योमा एयरबेस



चर्चा में क्यों?

- भारत-चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर अपनी रक्षा तैयारियों को बढ़ाते हुए, लद्दाख में मुध-न्योमा एयरबेस को संचालित किया।



मुख्य बिन्दु:

- **अवस्थिति:** यह एयरबेस पूर्वी लद्दाख के लेह जिले के न्योमा में 13,700 फीट (4,200 मीटर) की ऊँचाई पर स्थित है, जो इसे दुनिया के सबसे ऊँचे लड़ाकू-सक्षम एयरफील्ड में से एक बनाता है।
- **निर्माण:** सीमा सड़क संगठन
- **महत्त्व:** एलएसी से इसकी निकटता भारत को महत्त्वपूर्ण सामरिक और सैन्य लाभ प्रदान करती है, जिससे डेपसांग मैदान, पैगोंग त्सो और चुशुल घाटी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में त्वरित प्रतिक्रिया, बल प्रक्षेपण और उन्नत निगरानी संभव हो पाती है।
- **लद्दाख में चौथा प्रमुख एयरबेस:** यह लेह, कारगिल और थोइस एयरबेस के पूरक के रूप में कार्य करेगा।



अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य



भारत और नेपाल संबंध



चर्चा में क्यों?

- भारत, नेपाल ने व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और नेपाल ने भारत में जोगबनी और नेपाल में विराटनगर के बीच रेल-आधारित माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए पारगमन संधि में संशोधन किया है।



मुख्य बिन्दु:

- यह उदारीकरण प्रमुख पारगमन गलियारों - कोलकाता-जोगबनी, कोलकाता-नौतनवा (सुनौली), और विशाखापत्तनम-नौतनवा (सुनौली) तक फैला हुआ है।
- **उद्देश्य:** दोनों देशों के बीच बहुविध व्यापार संपर्क को मजबूत करना तथा तीसरे देशों के साथ नेपाल के व्यापार को बढ़ावा देना।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

सारंडा वन

चर्चा में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को पारिस्थितिक रूप से समृद्ध सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया।

मुख्य बिन्दु:

सारंडा के बारे में

- झारखंड स्थित सारंडा वन एशिया का सबसे बड़ा साल वन है, जो लगभग 820-900 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी पहाड़ी भू-भाग के कारण इसे "सात सौ पहाड़ियों की भूमि" के नाम से भी जाना जाता है।
- यह वन छोटानागपुर जैव-भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ के वनों के साथ एक प्राकृतिक परिदृश्य सातत्य बनाता है।
- इस क्षेत्र से होकर बहने वाली प्रमुख नदियों में कारो, कोइना, लैलौर आदि शामिल हैं।
- यहाँ दुर्लभ वनस्पति, ताड़, जंगली केले, फर्न, और पाइपर प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है, जिनमें स्थानिक साल वन कछुआ, चार सींग वाला मृग, एशियाई पाम सिवेट और जंगली हाथी शामिल हैं।
- यहाँ हो, मुंडा, उरांव और संबद्ध आदिवासी समुदाय निवास करते हैं, जिनकी आजीविका और सांस्कृतिक परंपराएँ आंतरिक रूप से वन उपज से जुड़ी हुई हैं।
- यह भारत के लौह अयस्क भंडार का 26% भी है।

जलवायु वित्त-पोषण लक्ष्य

चर्चा में क्यों?

- भारत ने स्पष्ट किया कि जलवायु वित्त-पोषण में कमी जलवायु कार्रवाई के लक्ष्यों को पूरा करने में प्रमुख बाधा है।

मुख्य बिन्दु:

- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (UNFCCC) के पक्षकारों का 30वाँ सम्मेलन (CoP30) ब्राजील के बेलेम में आयोजित किया जा रहा है।
- इस सम्मेलन के दौरान बेसिक (BASIC) तथा समान विचारधारा वाले विकासशील देशों (LMDC) के समूह की ओर से भारत ने बयान जारी किए और इसमें जलवायु वित्त पोषण की महत्ता को रेखांकित किया।
- **BASIC समूह के सदस्य:** ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन।
- **अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत जलवायु वित्त-पोषण लक्ष्य**
- **बाकू से बेलेम रोडमैप- 1.3 T (ट्रिलियन) लक्ष्य:** UNFCCC-CoP29 में पक्षकार देशों ने नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य पर सहमति व्यक्त की थी। इसमें विकासशील देशों के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम 300 बिलियन डॉलर जुटाने का लक्ष्य वर्ष 2035 तक प्राप्त करना भी शामिल है।
- इसमें एक व्यापक लक्ष्य वर्ष 2035 तक बाह्य वित्तीय सहायता बढ़ाकर प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन डॉलर करना भी शामिल है।
- **ग्लासगो जलवायु समझौता:** इसके तहत विकसित देशों ने यह वचन दिया कि वे वर्ष 2025 तक विकासशील देशों को जलवायु-अनुकूलन हेतु 40 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।

जलवायु परिवर्तन पर सूचना अखंडता पर घोषणा



चर्चा में क्यों?

- जलवायु परिवर्तन पर सूचना सत्यनिष्ठा के लिए वैश्विक पहल ने COP-30 में जलवायु परिवर्तन पर सूचना सत्यनिष्ठा पर घोषणा-पत्र जारी किया।



मुख्य बिन्दु:

- **पहल की शुरुआत:** वर्ष 2024 में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में इस पहल की घोषणा की गई थी। यह देशों एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच एक समर्पित बहुपक्षीय सहयोग है। इसका उद्देश्य जलवायु संबंधी मुद्दों पर सूचना सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने वाले अनुसंधान और कार्रवाई को वित्त-पोषित करना है।
- इसने जलवायु परिवर्तन पर सूचना सत्यनिष्ठा के लिए एक वैश्विक कोष भी गठित किया है।

⌚ विज्ञान प्रौद्योगिकी 🌡️

ऑरोरा

📢 चर्चा में क्यों?

- कैनिबल सौर तूफान के कारण उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि में ऑरोरा की घटनाएँ घटित हुई हैं।

📌 मुख्य बिन्दु:

- कैनिबल सौर तूफान एक शक्तिशाली अंतरिक्ष मौसम घटना है। यह तब घटित होती है, जब दो या दो से अधिक सौर तूफान एक-दूसरे के साथ टकराते हैं और विलीन हो जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप, एक अधिक शक्तिशाली तूफान उत्पन्न होता है, जो जीपीएस और विद्युत प्रणालियों को प्रभावित करता है।

ऑरोरा (Aurora)

- ऑरोरा रात्रि के आकाश में दिखाई देने वाली एक प्राकृतिक प्रकाश की घटना है, जो आमतौर पर केवल निचले ध्रुवीय क्षेत्रों में घटित होती है।
- ऑरोरा की परिघटना ऊपरी वायुमंडल के परमाणुओं के सौर पवन के आवेशित कणों (इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन) के संपर्क में आने के कारण घटित होती है।
- उत्तरी ध्रुव के पास, इसे ऑरोरा बोरेलिस कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव के पास, इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है।

आर्थिक परिदृश्य

महत्त्वपूर्ण खनिजों की नई रॉयल्टी दरें

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चार महत्त्वपूर्ण खनिजों - सीजियम, ग्रेफाइट, रुबिडियम और जिर्कोनियम की रॉयल्टी दर को निर्दिष्ट/संशोधित करने को मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिन्दु:

महत्त्वपूर्ण खनिज

- ये आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं, और इन खनिजों की उपलब्धता की कमी या कुछ भौगोलिक स्थानों में निष्कर्षण या प्रसंस्करण का संकेन्द्रण संभावित रूप से "आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों और यहाँ तक कि आपूर्ति में व्यवधान" का कारण बन सकता है।
- वर्ष 2023 में, केंद्र ने लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, टिन और ताँबा सहित 30 महत्त्वपूर्ण खनिजों की पहचान की, जो देश के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं।

रॉयल्टी दर

- रॉयल्टी दर सरकार द्वारा खनन कम्पनियों पर पृथ्वी से खनिज निकालने के लिए लगाया जाने वाला शुल्क है।
- रॉयल्टी दरें खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 एवं खनिज रियायत नियम, 1960 द्वारा नियंत्रित होती हैं।
- ये कानून केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से परामर्श के बाद समय-समय पर रॉयल्टी दरें तय करने और संशोधित करने का अधिकार देते हैं।

महत्त्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट

वैश्विक कार्बन बजट, 2025

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने ग्लोबल कार्बन बजट 2025 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में भारत का कार्बन उत्सर्जन धीमी गति से बढ़कर 1.4% रहा। इसके लिए मानसून द्वारा ठंडक और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास को उत्तरदायी कारक माना गया है।

मुख्य बिन्दु:

- वर्ष 2024 में भारत तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक रहा। भारत ने वार्षिक रूप से 3.2 बिलियन टन कार्बन का उत्सर्जन किया है। इससे आगे केवल संयुक्त राज्य अमेरिका (4.9 बिलियन टन) और चीन (12 बिलियन टन) हैं।
- भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वार्षिक रूप से 2.2 टन है।
- प्रमुख योगदानकर्ता:** कोयला भारत के उत्सर्जन में योगदान देने वाला प्रमुख ईंधन प्रकार है।

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट, 2025</p> <ul style="list-style-type: none">विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट, 2025 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार, तपेदिक (टीबी) संपूर्ण विश्व में मृत्यु के शीर्ष 10 कारणों में से एक है। साथ ही, किसी एकल संक्रामक सूक्ष्मजीव से होने वाली मृत्यु का एक प्रमुख कारण भी है।
2.	<p>प्रत्यूष सिन्हा समिति</p> <ul style="list-style-type: none">हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की थी। इसकी अध्यक्षता प्रत्यूष सिन्हा कर रहे थे।इस समिति ने सेबी के भीतर शीर्ष अधिकारियों के बीच हितों के टकराव को रोकने के लिए मजबूत नियमों की सिफारिश की है।

